

आर्टिकल 15

संदर्भ

देश में हर वर्ष हज़ारों फ़िल्में बनती हैं और इनमें से कुछ समय-समय पर चर्चा तथा विवाद का विषय बन जाती हैं। इसी कड़ी में हाल ही में रिलीज़ हुई अनुभव सनिहा और गनिगार शंकर नरिदेशति फ़िल्म आर्टिकल 15 लगातार चर्चा में बनी हुई है। बताया जा रहा है कथिह फ़िल्म सचची घटनाओं से प्रेरति है, लेकनि इसके कंटेंट को लेकर कई लोगों को आपत्तभी है। सवर्णों के एक संगठन ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। फ़िल्म में उत्तर प्रदेश के एक गाँव की कहानी दर्शाई गई है और इसका टाइटल संविधान के अनुच्छेद 15 से लिया गया है।

आर्टिकल 15 क्या है?

संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में देश के सभी नागरिकों को समता यानी समानता का मौलिक अधिकार देने की बात कही गई है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिये गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है कहर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव न हो।

आर्टिकल 15 के चार प्रमुख बंदि

1. आर्टिकल 15 के नयिम 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
2. नयिम 2 के मुताबकि, किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रजिस्टर्स में जाने से नहीं रोका जा सकता।
3. वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उनसे भेदभाव नहीं कथिा जा सकता, लेकनि महिलाओं और बच्चों को इस नयिम में अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। आर्टिकल 15 के नयिम 3 के मुताबकि, अगर महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष उपबंध कथिे जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। महिलाओं के लिये आरक्षण या बच्चों के लिये मुफ्त शकिषा इसी उपबंध के तहत आते हैं।
4. इस आर्टिकल के नयिम 4 के मुताबकि, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पछिड़े तथा SC/ST/OBC के लिये विशेष उपबंध बनाने की छूट है।

क्यों हो रहा है विवाद?

फ़िल्म आर्टिकल 15 समाज में मौजूद ऊँच-नीच एवं जातगत भेदभाव पर आधारति है और यही वज़ह है कथि एक वर्ग विशेष के कुछ संगठन इसका वरिोध कर रहे हैं। आज भी जातगत भेदभाव की घटनाएँ यदा-कदा सामने आ जाती हैं और इसी से नपिटने के लिये नागरिकों को मलिा है आर्टिकल 15 यानी ऐसा मौलिक अधिकार जसिके तहत किसी भी भारतीय नागरिक से उसके धर्म, नसल, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कथिा जा सकता। सरकार और समाज की यह जमिमेदारी है कथिऐसा कोई भेदभाव न होने दे। आज भी जाति और धर्म के नाम पर आर्टिकल 15 का सबसे ज्यादा उल्लंघन कथिा जाता है। महानगरों और बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लगता है कथि जाति और धर्म के नाम पर अब भेदभाव लगभग खत्म हो गया है, लेकनि सच तो यह है कथि देश के कई हिस्सों में इस तरह का भेदभाव अभी भी होता है। जाति और धर्म को लेकर समाज में सदथियों से व्याप्त धारणाएँ आज भी मौजूद हैं।

आर्टिकल 15 के बेहतर अनुपालन हेतु बनाए गए कुछ कानून

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (The Protection of Civil Rights Act, 1955): इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात् छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। वर्ष 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया गया था। यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था, लेकनि अप्रैल 1965 में गठति इलायापरमूल समति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन कथिे गए तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया था। यह संशोधति अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से प्रभावी हुआ और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप है।

अनुसूचति जाति एवं अनुसूचति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989): यह अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचति जातियों और अनुसूचति जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिये विशेष न्यायालय बनाने तथा राहत देने और ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिये प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिये वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किये गए तथा यह 26 जनवरी, 2016 से लागू हुआ।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (Hindu Succession Act, 1956): इस अधिनियम में बताया गया है कि जब किसी हिंदू व्यक्तिकी मृत्यु बनिा वसीयत कयि हो जाती है, तो उसकी संपत्तिको उसके वारसियों, परजिनों या रशितेदारों में कानूनी रूप से कसि तरह बाँटा जाएगा। अधिनियम में मृतक के उत्तराधिकारियों को अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा गया है और मृतक की संपत्ति में उनको मिलने वाले हसिसे के बारे में भी बताया गया है। यह कानून जनम से हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सखि या ऐसा कोई व्यक्ती जसिने इनमें से कोई धर्म अपना लयिा हो, पर लागू होता है। वर्ष 2005 में इस कानून में संशोधन कयिा गया तथा संपत्तिके मामले में पुत्रियों को भी बराबर का हक दयिा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कयिा कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधति) अधिनियम के तहत 9 सतिंबर 2005 को जीवति करताओं की जीवति पुत्रियों को संपत्ति में हसिसा लेने का अधिकार है। इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि ऐसी पुत्रियों का जनम कब हुआ है।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (Maternity Benefit Act, 1961): यह अधिनियम मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है अर्थात अपने बच्चे की देखभाल के लिये पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थति रहने की सुविधा देता है। यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। वर्ष 2017 में इस अधिनियम में संशोधन कयिे गए। इसके तहत कामकाजी महिलाओं को दो बच्चों के लिये मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और दो से अधिक बच्चों के लिये 12 सप्ताह कर दी गई है। 'कमशिनगि मदर' और 'एडॉप्टगि मदर' को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मल्लिगा तथा घर से काम करने की सुविधा दी गई है। इसके साथ 50 या उसके अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच का अनविरय प्रावधान कयिा गया है।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और निवारण) अधिनियम, 2013 [Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013]: संवधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत लगि समानता की गारंटी में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने का अधिकार शामिल है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और निवारण) अधिनियम, 2013 में एक नागरिक के रूप में समान, सुरक्षति और नरिापद वातावरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य अपनाने का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित कयिा गया है। इसके लागू हो जाने के बाद वषिनिन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पर दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। यह कानून समय के अनुकूल है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने में यह उचित सहायता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में ऐतिहासिक वशिाखा बनाम राजस्थान सरकार मुकदमे का नरिणय देते समय ऐसे कानून की कमी महसूस की थी।

दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016): इस अधिनियम में दवियांगजनों के अधिकारों और वशिष अधिकारों की रक्षा के लिये व्यापक प्रावधान कयिे गए हैं। इन प्रावधानों में सेवाओं में आरक्षण बढ़ाना और अधिनियम के तहत दवियांगता की अतरिकित 14 श्रेणियों को शामिल कयिा गया है। इन 14 श्रेणियों में ऐसडि अटैक पीड़ति, थैलेसीमयिा, हमिीफीलयिा, अवुरुद्ध वकिस, सीखने की असमर्थता और पार्कसिन बीमारी भी शामिल हैं। नए प्रावधान और दवियांगता की श्रेणियाँ वर्ष 2007 के संयुक्त राष्ट्र समझौते की सफिरशियों के अनुरूप तय की गई हैं। भारत इन सफिरशियों पर हस्ताक्षर कर चुका है।

मानसक सवास्थ्य अधिनियम, 2017 (The Mental Health Care Act, 2017): यह अधिनियम मानसक सवास्थ्य के इलाज के तरीके को बदलने का प्रयास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारा कानून दवियांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समेलन (UNCRPD) के अनुरूप हो। यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसका उद्देश्य मानसक रूप से बीमार लोगों को मानसक सवास्थ्य देखभाल एवं सेवाएँ मुहैया कराना है। साथ ही देखभाल एवं सुविधाएँ देते समय ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना भी इसके उद्देश्यों शामिल है। इसके तहत मानसक रोगियों के अधिकार, अग्रमि नरिदेश, केंद्रीय और राज्य मानसक सवास्थ्य अथॉरिटी, मानसक सवास्थ्य प्रतिष्ठान, मानसक सवास्थ्य समीक्षा आयोग और बोर्ड, आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से अलग करना तथा बजिली के झटके की उपचार पद्धति को नषिदिध करना आदि प्रावधानों की व्यवस्था की गई है।

क्या हैं मौलिक अधिकार?

- मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्तिके जीवन के लिये अनविरय होने की वज़ह से संवधान द्वारा नागरिकों को प्रदान कयिे गए हैं और जनिमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं कयिा जा सकता।
- ये ऐसे अधिकार हैं जो कसिी के व्यक्तित्व के पूरण वकिस के लिये आवश्यक हैं और जनिके बनिा मनुष्य अपना पूरण वकिस नहीं कर सकता।
- इन अधिकारों को मौलिक इसलिये कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संवधान में स्थान दयिा गया है तथा संवधान में संशोधन की प्रक्रयिा के अतरिकित इनमें कसिी भी प्रकार से संशोधन नहीं कयिा जा सकता।
- ये अधिकार व्यक्तिके प्रत्येक पक्ष के वकिस हेतु मूल रूप में आवश्यक हैं तथा इनके अभाव में व्यक्तिके व्यक्तित्व का वकिस अवुरुद्ध हो जाएगा।
- इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कयिा जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्तिको समान रूप से प्राप्त होते हैं।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

भारतीय संवधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संवधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक कयिा गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44वाँ संशोधन होने से पहले संवधान में दयिे गए मौलिक अधिकारों की सात श्रेणियाँ थीं, परंतु इस संशोधन के द्वारा संपत्तिके अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दयिा गया।

छह मौलिक अधिकार

- 1. समानता का अधिकार:** इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जात/लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का नषिध तथा रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल है।
- 2. स्वतंत्रता का अधिकार:** भाषा और वचिार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, एकत्र होने संघ या यूनियन बनाने, आने-जाने, नविस करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, वदिशों के साथ भन्नितापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के तहत दयि जाते हैं)।
- 3. शोषण के वरिद्ध अधिकार:** इसमें बेगार, बाल शर्म और मनुष्यों के व्यापार का नषिध कयिा गया है।
- 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार:** आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अनुयायी बनना, उस पर वशिवास करना एवं धर्म का प्रचार करना इसमें शामिल हैं।
- 5. सांस्कृतिक तथा शक्ति संबंधी अधिकार:** किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षति रखने, भाषा या लपि बचाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएँ चलाने का अधिकार।
- 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार:** मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लयि संवैधानिक उपचार का अधिकार।

बेशक आर्टिकल 15 समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन आज भी देश में बड़े पैमाने पर जातगत भेदभाव होता है, वशिषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जात के नचिले पायदान पर खड़े समाजों, वशिषकर दलति समुदाय के लोगों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार कयिा जाता है। भारत की आबादी में दलतियों की हसिसेदारी लगभग 16% है और लगभग तीन हज़ार वर्ष पुरानी जातव्यवस्था भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है।

अभ्यास प्रश्न: संवैधान प्रदत्त आर्टिकल 15 के प्रभावी कार्यान्वयन से जातगत भेदभाव को कम कयिा जा सकता है। चर्चा करें।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/article-15>

